

मं० प्रो.वि./एफ.डी./०३-८४/३९०८८.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं० राजेन्द्रा वेपर मित्त॑, '५० इन्डस्ट्रीयल एन्ड फरीदावाद के श्रमिक श्री राम धनी शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, ग्रौदोगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई अवित्यों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके "द्वारा" सरकारी अधिसूचना सं० ५४१५-३-श्रम-६८/१५२५४, दिनांक २० जून, १९६८ के बाथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० ११४९५-जी-श्रम-४४-श्रम/५७/११२४५, दिनांक ७ फरवरी, १९५८ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदावाद, को विवादग्रस्त या उससे सुरंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुरंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री राम धनी शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

एस० के० महेश्वरी,  
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम विभाग।

श्रम विभाग

प्रादेश

दिनांक १९ अक्टूबर, १९८४

मं० प्रो.वि./एफ.डी./८-८४/३९०४६.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं० एस्कोर्ट लि० पनाट नं० १, १८/४, मधुरा रोड, फरीदावाद के श्रमिक श्री आर० के० भाटिया तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, ग्रौदोगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई अवित्यों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ५४१५-३-श्रम-६८/१५२५४, दिनांक २० जून, १९६८ के बाथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० ११४९५-जी-श्रम-४४-श्रम/५७/११२४५, दिनांक ७ फरवरी, १९५८ द्वारा अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदावाद, को विवादग्रस्त या उससे सुरंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुरंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री आर० के० भाटिया की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं; तो वह किस राहत का हकदार है?

मं० प्रो.वि./एफ.डी./१५३-८४/३९०५३.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं० श्रीयंटल हाइकोर्ट ज२/७ मधुरा राट फरीदावाद, के श्रमिक श्री भाष्ठो गिह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई अंतर्विध विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, ग्रौदोगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई अवित्यों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ५४१५-३-श्रम-६८/१५२५४, दिनांक २० जून, १९६८ के बाथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० ११४९५-जी-श्रम-४४-श्रम/५७/११२४५, दिनांक ७ फरवरी, १९५८ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदावाद, को विवादग्रस्त या उससे सुरंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुरंगत प्रश्नवा० अंतर्विध मामला है:—

क्या श्री भाष्ठो गिह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं; तो वह किस राहत का हकदार है?